

न्यूज़ हुडे

डिजिटल पब्लिक गुड्स (DPGs), डिजिटल बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने का नया तरीका है

- संयुक्त राष्ट्र द्वारा डिजिटल पब्लिक गुड्स (DPGs) को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन डेटा, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल, ओपन स्टैंडर्ड और ओपन कंटेंट के रूप में परिभाषित किया गया है। ध्यातव्य है कि ये सभी गोपनीयता संबंधी नियमों का पालन करते हैं तथा इनका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों (SDG) को प्राप्त करना है।
- वे गैर-अपवर्जित (non-excludable) (सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध) और गैर-प्रतिद्वंद्वी (non-rivalrous) प्रकृति के होते हैं (अधिक लोगों द्वारा उनका उपभोग करने के उपरांत भी उनकी आपूर्ति में कमी नहीं होती है)।
- DPG के उदाहरणों में एक जिला स्वास्थ्य सूचना सॉफ्टवेयर 2 (DHIS-2) शामिल है। यह स्वतंत्र तथा मुक्त स्रोत स्वास्थ्य प्रबंधन डेटा प्लेटफॉर्म है। इसका उपयोग विभिन्न संगठनों सहित कुल 54 देशों द्वारा किया जाता है।
- ये डिजिटल बाजारों के प्रत्यक्ष विनियमन के विकल्प या संपूरक हैं। ये बाजार संकेंद्रण से ग्रस्त हैं तथा लोक कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करते हैं।
- डिजिटल बाजारों में प्रतिस्पर्धा के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत में किए गए प्रयासः
 - सार्वभौमिक सेवा दायित्व— यह क्रॉस-सब्सिडी का एक रूप है। इसके माध्यम से राज्य यह सुनिश्चित करते हैं कि ग्रामीण और लाभहीन क्षेत्रों की भी दूरसंचार सेवाओं तक पहुंच स्थापित हो।
 - ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) पहलः इसका उद्देश्य विभिन्न ई-कॉमर्स प्रणालियों को एकल समाधान तंत्र में एकीकृत करना है।
 - डेटा एंपावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर (DEPA) का उद्देश्य सहमति प्रबंधक (Consent Manager: CM) नामक मध्यस्थ के माध्यम से डेटा नियंत्रकों और डेटा उपयोगकर्ताओं के मध्य निर्बाध डेटा स्थानांतरण की अनुमति प्रदान कर डेटा की अनावश्यक गोपनीयता को भंग/निष्क्रिय करना है।



○ इसके कार्यान्वयन में विद्यमान चुनौतियाँ: साइबर सुरक्षा, प्रौद्योगिकी परिष्करण के मुद्दे, लागत संबंधी चुनौती, कौशल की कमी, नवाचार के लिए निजी अभिकर्ताओं के इष्टतम प्रोत्साहन का अभाव और साइबर सुरक्षा से संबंधित मुद्दे इत्यादि।

शिक्षक पर्व के अवसर पर प्रधान मंत्री ने विद्यांजलि 2.0 और शिक्षा क्षेत्र में अन्य प्रमुख पहलों का शुभारंभ किया

- 'शिक्षक पर्व' शिक्षकों के योगदान के महत्व को रेखांकित करने के लिए मनाया जा रहा है।
 - 'शिक्षक पर्व-2021' का विषय "क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल्स: लर्निंग फ्रॉम स्कूल्स इन इंडिया" है।
- प्रधान मंत्री ने शिक्षक पर्व के अवसर पर एक शैक्षिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए विभिन्न पहलों का शुभारंभ किया।
- शुभारंभ की गई महत्वपूर्ण पहलेंः
 - विद्यांजलि 2.0 पोर्टलः यह विद्यालयों के विकास और सुधार के उद्देश्य से निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) निधि तथा स्वयं सेवा के माध्यम से प्राप्त योगदान एवं दान आदि की सुविधा प्रदान करेगा।
 - केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की विद्यालयी गुणवत्ता आश्वासन और आकलन रूपरेखा (School Quality Assurance and Assessment Framework- SQAAF): यह CBSE से संबद्ध विद्यालयों में पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र, आकलन, बुनियादी ढांचे, समावेशी प्रथाओं और अभिशासन प्रक्रिया जैसे आयामों में सामान्य मानकों को प्राप्त करने के लिए वैश्विक मानदंड निर्धारित करेगा।
 - दिव्यांगों के लिए शैक्षिक उपकरणः भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश (श्रवण बाधितों के लिए ऑडियो और पाठ/ टेक्स्ट आधारित सांकेतिक भाषा वीडियो ज्ञान के सार्वभौमिक डिजाइन के अनुरूप), बोलने वाली किताबें (टॉकिंग बुक्स, नेत्रहीनों के लिए ऑडियो किताबें) इत्यादि।
- पूर्व में आरंभ की गई अन्य महत्वपूर्ण पहलेंः
 - 'समझ के साथ पढ़ने तथा संख्या गणना में निपुणता के लिए राष्ट्रीय पहल (निपुण भारत) (National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy: NIPUN) के लिए स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र प्रगति के लिए राष्ट्रीय पहल (NISHTHA/निष्ठा) 'निष्ठा 2.0' शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम।
 - संपूर्ण देश को एक डिजिटल तथा तकनीकी ढांचा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला (National Digital Education Architecture: NDEAR) एवं राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच (NETF)।



- NDEAR 2021 छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों व शैक्षिक समुदायों को लाभान्वित करने वाले विविध, प्रासंगिक, संदर्भित एवं अभिनव समाधान निर्मित करने तथा उन्हें वितरित करने हेतु डिजिटल शिक्षा तंत्र को सक्रिय एवं उत्प्रेरित करने के लिए रूपरेखा तैयार करता है।
- UPI इंटरफेस ने जिस प्रकार बैंकिंग क्षेत्र को क्रांतिकारी बनाने का कार्य किया है, उसी प्रकार N-DEAR भी सभी विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों के मध्य 'सुपर-कनेक्ट' के रूप में कार्य करेगा।

रक्षा मंत्रालय ने राजस्व अधिप्राप्ति हेतु सशस्त्र बलों को वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन को स्वीकृति प्रदान की

- **रक्षा सेवाओं को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन (Delegation of Financial Powers to Defence Services: DFPDS), 2021** सशस्त्र बलों को राजस्व अधिप्राप्ति शक्तियों के मामले में संवर्धित अधिकार प्रदान करता है।
 - राजस्व खरीद (अधिप्राप्ति) में नवीकरणों और प्रतिस्थापनों सहित सेवा में पहले से स्वीकृत संपत्तियों की खरीद भी शामिल है।
- **DFPDS 2021 का उद्देश्य**, क्षेत्रीय टुकड़ियों को सशक्त बनाना; परिचालन संबंधी तैयारियों पर विशेष ध्यान देना तथा व्यावसायिक गतिविधियों में सुगमता व सेवाओं के मध्य संयुक्तता को बढ़ावा देना है।
- **DFPDS 2021 का महत्व**
 - तत्काल परिचालन संबंधी आवश्यकताओं और आवश्यकता निर्वाह संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए त्वरित तरीके से उपकरण/युद्धक भंडार खरीदने हेतु फील्ड कमांडरों और उससे निचले स्तर के अधिकारियों को सशक्त बनाना।
 - देश के सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ करना।
 - प्रक्रियात्मक अवरोधों का निवारण करने हेतु अधिक विकेंद्रीकरण तथा परिचालन संबंधी दक्षता सुनिश्चित करना।
 - सभी स्तरों पर त्वरित निर्णयन तथा संसाधनों के इष्टतम उपयोग में सहायता प्रदान करना।
- **हथियारों की खरीद में सरकार द्वारा की गई अन्य पहलें:**
 - **रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (Defence Acquisition Procedure), 2020:** प्रदर्शन, क्षमताओं एवं गुणवत्ता मानकों के संदर्भ में सशस्त्र बलों द्वारा आवश्यक सैन्य उपकरणों, प्रणालियों तथा प्लेटफॉर्मों का समय पर अधिग्रहण सुनिश्चित करना। यह अधिग्रहण आवंटित बजटीय संसाधनों के इष्टतम उपयोग के माध्यम से संपन्न किया जाएगा।
 - **रक्षा निवेशक प्रकोष्ठ (Defence Investor Cell):** रक्षा क्षेत्र में निवेश हेतु निवेश के अवसरों, प्रक्रियाओं एवं विनियामक आवश्यकताओं से संबंधित प्रश्नों को संबोधित करने सहित अन्य जानकारी प्रदान करना।

भारत और फ्रांस ने अंतरिक्ष सुरक्षा वार्ता (Space Security Dialogue: SSD) के आयोजन पर सहमति व्यक्त की है

- भारत के लिए यह द्विपक्षीय अंतरिक्ष सुरक्षा वार्ता का तीसरा संस्करण है। इससे पूर्व, भारत ने दो देशों यथा—जापान (2019) और संयुक्त राज्य अमेरिका (2015) के साथ भी ऐसी वार्ता का आयोजन किया है।
 - फ्रांस के लिए भारत प्रथम एशियाई देश होगा, जिसके साथ वह इस प्रकार की वार्ता आयोजित करेगा।
 - अंतरिक्ष और परमाणु क्षेत्रों में भारत और फ्रांस के मध्य स्थापित सहयोग, दोनों देशों के एक दूसरे के प्रति गहन विश्वास की ओर संकेत करता है।
- SSD के माध्यम से, दोनों देश उभरते हुए अंतरिक्ष परिवेश और बाह्य अंतरिक्ष तक सुरक्षित, कुशल, सतत व निरंतर पहुंच के समक्ष संभावित खतरों की एक साझी बहुपक्षीय समझ विकसित करेंगे।
- **SSD का महत्व**
 - भारत के अंतरिक्ष संबंधी अभिविन्यास में परिवर्तन का संकेत: भारत की विभिन्न देशों के साथ असैन्य अंतरिक्ष सहयोग संलग्नता अंतरिक्ष सुरक्षा पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए विकसित हुई है।
 - यह अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन द्वारा काउंटर-स्पेस क्षमताओं का शीघ्रता से विकास करना भारत, फ्रांस, जापान और अमेरिका के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न करता है।
 - SSD वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणालियों, अंतरिक्ष संबंधी स्थितिजन्य जागरूकता, अंतरिक्ष सुरक्षा, बाह्य अंतरिक्ष परिवेश की संधारणीयता और बाह्य अंतरिक्ष में टकराव से बचाव को संबोधित करने हेतु भी महत्वपूर्ण है।
 - समान विचारधारा वाले भागीदारों के साथ इस प्रकार की वार्ता से भारत को वैश्विक अभिशासन में एक प्रमुख नेतृत्व की भूमिका प्राप्त होगी।

एक अध्ययन के अनुसार भारत में तीन नए हीटवेव हॉटस्पॉट्स ने विशाल आबादी के समक्ष तत्काल स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न कर दिया है

- “इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्लाइमेटोलॉजी” नामक पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन ने भारत में हीट वेव और गंभीर श्रेणी के हीट वेव के संयोजन के साथ मृत्यु दर के संबंध को रेखांकित किया है।

○ मुख्य निष्कर्ष

- **हीटवेव एक घातक स्वास्थ्य संकट:** इसके कारण हाल के दशकों में विश्व भर में व्यापक जन हानि हुई है। भारत में भी विगत आधी शताब्दी में इन मौसमी घटनाओं की आवृत्ति, तीव्रता एवं इनके प्रभाव की अवधि में वृद्धि हुई है।
- **हीट वेव की स्थानिक-सामयिक प्रवृत्ति में परिवर्तन:** भारत के पूर्वी भाग में गंगा घाटी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल पश्चिम बंगाल और बिहार के क्षेत्र से लेकर उत्तर-पश्चिमी, मध्य और आगे दक्षिण-मध्य क्षेत्र की ओर परिवर्तन दर्ज किया गया है।

○ हीट वेव (ऊष्मीय तरंगें):

- हीट वेव की स्थिति तब मानी जाती है, जब किसी एक स्थान पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक (मैदानी भागों में) तथा कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक (पहाड़ी क्षेत्रों में) हो जाता है।
- हीट वेव का स्वास्थ्य, कृषि, अर्थव्यवस्था एवं बुनियादी ढांचे पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।

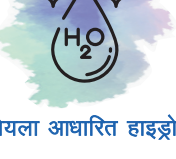
○ हीट वेव को नियंत्रित करने हेतु सरकार की रणनीतियाँ:

- पूर्व चेतावनी प्रणाली तथा विभिन्न एजेंसियों / विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करना।
- स्वास्थ्य कर्मियों के लिए क्षमता निर्माण / प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

○ भारत-फ्रांस अंतरिक्ष सहयोग:

- फ्रांस, वर्ष 2022 तक भारत के मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों हेतु चिकित्सा सहायता और उनके प्रशिक्षण में भारत की सहायता कर रहा है।
- **अंतरिक्ष जलवायु वेधशाला (Space Climate Observatory):** जलवायु परिवर्तन का सामना करने में उनके सहयोग को बढ़ाने हेतु अभिकल्पित है।
- **थर्मल इन्फ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेज़ल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट (तृष्णा) (Thermal infraRed Imaging Satellite for High resolution Natural resource Assessment: TRISHNA):** यह जल चक्र की निगरानी के माध्यम से इसका उपयोग करने के उचित विकल्प खोजने में सहायता करेगा।
- **मेघा-ट्रोपिक्स:** उष्णकटिबंधीय वातावरण और मानसून, चक्रवात आदि जैसे पक्षों से संबंधित जलवायु का अध्ययन करना।
- **एर्गोस और एल्टिका से संबद्ध उपग्रह (सरल) (Satellite with ARGOS and ALTIKA (SARAL)):** इसे तुंगतामिति मापक (altimetry) का उपयोग करके अंतरिक्ष से समुद्रविज्ञान का अध्ययन करने के लिए वर्ष 2013 में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था।

अन्य सुर्खियाँ

 कृषि अवसंरचना कोष (AIF)	○ केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने राज्यों से AIF का लाभ उठाने हेतु आग्रह किया है, ताकि गोदाम व शीत भंडारण की सुविधा से विहीन लघु एवं सीमांत किसानों को सहायता प्रदान की जा सके। ○ कृषि अवसंरचना कोष के तहत केंद्रीय क्षेत्र की वित्तपोषण सुविधा संबंधी योजना के बारे में – ➤ उद्देश्य— इसका उद्देश्य फसल कटाई उपरांत प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों में निवेश के लिए मध्यम-दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा प्रदान करना है। ➤ यह वर्ष 2020-21 से वर्ष 2029-30 तक की अवधि के लिए लागू रहेगी। ➤ प्राथमिक कृषि साख समितियों (Primary Agricultural Credit Societies: PACS), विपणन सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों (Farmer Producers Organizations: FPOs) आदि को ऋण के रूप में एक लाख करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे।
 टी+1 (व्यापार + 1 दिन) निपटान चक्र [T+1 (Trade plus 1 day) settlement cycle]	○ भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी/SEBI) ने बाजारों के लिए एक वैकल्पिक T+1 निपटान चक्र प्रस्तुत किया है। ➤ T+1 से यह तात्पर्य है कि वास्तविक लेनदेन होने के एक दिन के भीतर ही निपटान को स्वीकृति प्रदान करनी होगी। ➤ यह 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। ➤ इसके द्वारा बाजार की तरलता और ट्रेडिंग टर्नओवर में बढ़ोतरी होने तथा निपटान जोखिम एवं ब्रोकर डिफॉल्ट्स/चूक के कम होने से घरेलू निवेशकों को लाभ पहुंचने की संभावना व्यक्त की गई है। ➤ T+2 निपटान चक्र पर वापस जाने के लिए, स्टॉक एक्सचेंज को बाजार को एक माह पूर्व नोटिस देना होगा।
 कोयला आधारित हाइड्रोजन	○ कोयला मंत्रालय ने कोयला आधारित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए एक रोड मैप तैयार करने हेतु एक टास्क फोर्स और विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। ○ प्राकृतिक गैस द्वारा हाइड्रोजन निर्माण (ग्रे हाइड्रोजन) और विद्युत-अपघटन के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा हाइड्रोजन निर्माण (ग्रीन हाइड्रोजन) के अतिरिक्त कोयला, हाइड्रोजन निर्माण (ब्राउन हाइड्रोजन) हेतु उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। ➤ कोयले को अन्यत्र प्रोत्साहित नहीं किया गया है, क्योंकि कोयले के माध्यम से हाइड्रोजन उत्पादन के दौरान कार्बन उत्सर्जन (कोयले में निहित नमी से) होने की संभावना बनी रहती है।
 जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु पहल	○ भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड/TRIFED), विदेश मंत्रालय के सहयोग से विश्व के विभिन्न देशों में संचालित/स्थित 75 भारतीय मिशनों/दूतावासों में आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर्स स्थापित करने की दिशा में प्रयासरत है। ध्यातव्य है कि इन कॉर्नर्स को आगामी 90 दिनों में स्थापित किया जाएगा। ➤ इन कॉर्नर्स को प्राकृतिक और जैविक उत्पादों के अतिरिक्त भौगोलिक संकेतक (GI) टैग प्राप्त जनजातीय कला एवं शिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष स्थान के रूप में चिन्हित किया जाएगा। ○ ट्राइफेड जनजातीय उत्पादों के साथ-साथ GI टैग उत्पादों को बढ़ावा देने और जनजातीय कारीगरों के सशक्तीकरण के प्रतीक के रूप में उन्हें एक ब्रांड में परिवर्तित करने के लिए कई मंत्रालयों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है।
 वतन प्रेम योजना	○ इस योजना को गुजरात सरकार द्वारा भारत से बाहर अधिवासित गुजरात के लोगों (NRIs) को उनके पैतृक गांवों में विकास कार्यों के लिए दान करने में सहायता प्रदान करने हेतु आरंभ किया गया है। ○ ऐसे NRIs ग्राम-स्तरीय परियोजना की लागत का 60% योगदान कर सकते हैं, जबकि शेष राज्य सरकार (40%) द्वारा वहन किया जाएगा। ○ इस योजना में ग्रामीण स्तर की परियोजनाएं जैसे स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं, सामुदायिक हॉल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आदि शामिल होंगी। ○ लक्ष्य— दिसंबर 2022 तक ₹1000 करोड़ की विकास परियोजनाएं तैयार करना।
 ओडिशा का विद्यालय रूपांतरण कार्यक्रम	○ 100 करोड़ रुपये के निवेश के माध्यम से ओडिशा सरकार द्वारा एक आइकॉनिक (iconic) विद्यालय स्थापित किया जाएगा। ○ राज्य के प्रत्येक क्षेत्र से विद्यालय में लगभग 1000 छात्रों (कक्षा 11वीं में 500 और 12वीं में 500 छात्र) को शामिल किया जाएगा। ○ यह अखिल भारतीय परीक्षाओं में छात्रों को सफलता दिलाने में मदद करेगा। विद्यालयों को भाषा प्रयोगशालाओं, स्मार्ट क्लास, गणित और उच्च तकनीक वाले कंप्यूटर एप्लीकेशन केंद्रों से युक्त किया जाएगा। ○ अंग्रेजी में निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए ब्लॉक स्तर पर स्थापित ओडिशा आदर्श विद्यालयों में परिवर्तन करके नयापन लाया जाएगा।

 ऑसिन्डेक्स (AUSINDEX)	○ यह रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी और भारतीय नौसेना के मध्य आयोजित किया जाने वाला एक द्विवार्षिक समुद्री युद्धाभ्यास है। इस वर्ष इसे ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जा रहा है।
 सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व	जयदेव ○ संस्कृति मंत्रालय ने "गीत गोविन्द" पर एक प्रदर्शनी के शुभारम्भ के साथ "गीत गोविन्द: जयदेव डिवाइन ओडिसी" नामक एक पुस्तक का भी विमोचन किया है। ○ जयदेव 12वीं सदी के एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक थे। इस सदी के दौरान उन्होंने एक संस्कृत कविता 'गीत गोविन्द' की रचना की थी। हालाँकि, वे केवल ओडिशा के पुरी धाम के भगवान श्रीकृष्ण या भगवान जगन्नाथ के ही परम भक्त थे। ○ गीत गोविन्द, भगवान श्री कृष्ण और राधा की मार्मिक प्रेम कथा पर आधारित एक रचना है। ○ इसे हिंदू धर्म के भक्ति आंदोलन के दौरान एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में संदर्भित किया गया था।

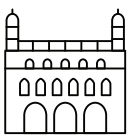
8468022022, 9019066066
www.visionias.in



 /c/VisionIASdelhi
  /Vision_IAS
  /visionias_upsc
  /VisionIAS_UPSC



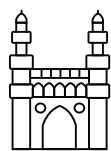
दिल्ली



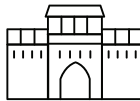
लखनऊ



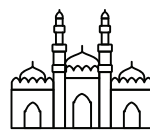
जयपुर



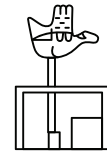
हैदराबाद



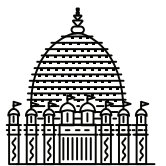
पुणे



अहमदाबाद



चंडीगढ़



गुवाहटी